on duty on that day was relieved from the service. It has been accepted by the incharge Regional Director, Eastern Zone there. The hon. Minister should come before this House as to what happened and what was the negligence on the part of the person in charge at the control tower. This explanation is necessary because this incident has taken place immediately after a week of the mid-air collision near Delhi. I hope the Minister would come with a clear statement as to how the person in charge of the control tower was relieved and how this accident was averted. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (Shrimati Renuka Chowdhury): Shrimati Veena Vermaji, not present.

PROGRESSIVE DECLINE IN FUND ALLOCATION FOR MODERNISATION OF INDIAN ARMY

श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर अपने इस स्पेशल मेंशन के जरिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश की सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण की गति न केवल मंद रही है वरन् रूक सी गई है। इसका कारण है, पिछले आठ वर्षों से इसके लिए बजट में आवंटित धनराशि में निरन्तर कमी होना। यह विचार मुझ जैसे किसी सुरक्षा प्रेमी का नहीं है वरन् भारत के वर्तमान स्थल सेनाध्यक्ष जनरल शंकर राय चौधरी और सेवा-निवृत स्थल सेनाध्यक्ष जनरल बी.एन. शर्मा का है, जिन्हें इस विषय में सर्वोच्च विशेषज्ञता प्राप्त है।

महोदया, उन्होंने यह विचार कल राजधानी में संपन्न एक विचार-गोष्ठी में व्यक्त किए। उनकी राय की कम से कम अब कोई उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप एवम् आतंकवादी गतिविधियों को खुला प्रोत्साहन देना, अफगानिस्तान की राजनैतिक अस्थिरता और पाकिस्तान द्वारा तालिबां मिलिशिया को पूर्ण सहायता आदि ऐसी बातें हैं, जिनके चलते हमारी स्थल सेना के आधुनिकीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

महोदया, पिछली सरकारों द्वारा सेना के लिए बजट में आवंटित धनराशि में निरन्तर कमी एक ऐसी गलती है, जिसे राष्ट्र कभी क्षमा नहीं कर सकता। एक ओर तो पूर्व प्रधानमंत्री एवम् वर्तमान प्रधानमंत्री सदन के भीतर और बाहर आश्वासन देते रहते हैं कि रक्षा बजट में कमी नहीं की जाएगी और दूसरी ओर आवंटन में निरंतर कमी की जाती रही है। कथनी और करनी के अन्तर का इससे बड़ा और घातक उदाहरण और क्या हो सकता है।

अंत में, मैं प्रधानमंत्री जी का आह्वान करता हूं कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस विषय पर दोनों सदनों में वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): श्री महेश्वर सिंह जी। .....श्री इकबाल सिंह जी।

Need to take Effective Measures for Air-Linking Jalandhar with Delhi Airport

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): मैडम, मैं इस विषय के बारे में पहले भी प्रश्नावली के माध्यम से और वैसे भी कई बार इस सदन में कह चुका हूं। तकरीबन 15 साल से पंजाब में इस चीज की डिमांड चली आ रही है कि जालंधर में एअरपोर्ट हो। ड्यूरिंग टेरेरिज्म पीरिएड यह कुछ बातें प्रेक्टीकली नहीं हो सकीं, लेकिन अब पंजाब में शांति हो गई है, उसके बावजूद भी हम बड़ी देर से मांग कर रहे हैं कि एअरपोर्ट खासकर के जालंधर में हो। जो कि दोआबा का इलाका है, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, करतारपुर, यहां के काफी लोग फारेन गए हुए हैं। मैडम, केरल और पंजाब दो ऐसी स्टेट हैं, जहां से बहुत लोग फारेन में गए हुए हैं और वे लोग वहां काम कर रहे हैं। पंजाब में जो फारेन करेन्सी देश के लिए आ रही है, वह पंजाब के लोग वहां काम करके यहां भेज रहे हैं, लेकिन एअरपोर्ट न होने की वजह से उनको बहुत मुश्किल आ रही है।

मैडम, जालंधर पंजाब राज्य का विकासशील औद्योगिक नगर है, जो प्रतिवर्ष काफी मात्रा में फारेन एक्सचेंज यहां लाता है। यह पंजाब सरकार का डिवीजनल सेंटर भी है और इसके साथ साथ जालंधर प्रेस सेंटर भी है।

जहां से पत्रकार दिल्ली के लिए काफी संख्या में आते-जाते हैं। इतना ही नहीं, जालंधर में आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन केन्द्र भी है। जालंधर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट न होने की वजह से सभी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पंजाब राज्य में कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में एक रेलवे कोच फैक्टरी भी है, एयरपोर्ट की फैसेलिटी न मिल पाने से यहां भी मुश्किल हो रही है। महोदय, जालंधर शहर पूरे नार्दन इंडिया के लिए फिल्म इंडस्ट्री का डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर है। इसमें कम से कम 600 से ऊपर इनके आफिसिस हैं, इनको भी बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि हैंडटूल्स, जो इस देश में से जाते हैं, बहुत ज्यादा गिनती में जालंधर से